(श्री विलास मुत्तेमवार)

मात्र इस योजना से महाराष्ट्र कम से कम चावल के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा।

इसी प्रकार की ह्यूमन रिवर प्रोजेक्ट तथा तुलतुली इर्रीगेशन प्रोजेक्ट हैं, जिन पर मात्र 37 करोड़ रुपये और 29 करोड़ रुपये व्यय होंगे किन्तु यह भी कागजी विचार चलने के कारण 4 वर्ष से लटक रही है।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह प्रधानमंत्रीजी की भावनाओं का आदर करते हुए और उनके 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना को तत्काल कार्यान्वित करायें ताकि देश को खाद्यान्न किसी भी हालत में आयात न करना पड़े वरन् हम निर्यात की ओर अग्रसर हो सकें।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर इस योजना को युद्ध स्तर पर पूरा करायें।

(ii) Need for protection of Bhakra Canal and financial assistance to the farmers afflicted by breach in canal.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, नहर भाखड़ा जो राष्ट्र की सम्पत्ति है और इस पर जो खर्चा लगा है, वह समूचे राष्ट्र का है। यह बात दूसरी है कि खुश हैसियती टैक्स किसानों से हरियाणा, पंजाब व राजस्थान में वसूला गया लेकिन यह समूचे राष्ट्र की सम्पत्ति है। इसको अगर कोई आघात पहुंचता है तो राष्ट्र के कलेजे पर चोट लगती है। पंजाब में आतंकवाद की आग से जब भारत की फौज जूझ रही थी, तब देश-द्रोहियों ने इस नहर को काटा और हरियाणा, पंजाब व राजस्थान को ने सिर्फ फसल से ही वंचित रखा बल्कि बच्चे, बूढ़े और पशु प्यास से व्याकुल रहे। बीमारी और मौत भी हुई। मरम्मत करवायी गयी। करोड़ों रुपये लगे। देशद्रोहियों ने फिर काट दी। अब फिर मरम्मत हो रही है। परन्तु देशद्रोही धमकी दे रहे हैं कि जो नहर की मरम्मत करेंगे, उन इन्जीनियरों को गोली से मार दिया जाये। यह देश को खुली चुनौती है। इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

जो पोस्टर छपे हैं, उनकी जांच हो तथा उन पर देशद्रोहियों को मुकदमा दर्ज किया जाये और उनकी प्रेस को जब्त किया जाये यथा उन देशद्रोहियों को सख्त सजा दी जाये। नहर की रक्षा राष्ट्रीय स्तर पर की जाये।

जो नुकसान हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के किसानों को हुआ है, सरकार राष्ट्रीय कोष से उसे दे। हर किस्म की वसूली व कर्जा राज्य सरकारें माफ करें और केन्द्र सरकार उनका भुगतान करे। जो फसल अब बोई जानी है, उसके लिये दूसरे दरियाओं से हरियाणा को पानी दिया जाये।

(iii) Need to streamline the management of various Schools in Tamil Nadu afficiated to Central Board of Secondary Education.

DR. A. KALANIDHI (Madras Central); The schools affiliated to the Central Board of Secondary Education are a separate category in the sense that neither the Central nor the State Government has any control over them. There is mushroom growth of these schools in Tamil Nadu. There are no fixed pay-scales for the staff

emyloyed in these schools. They are paid very meagre consolidated pay, the workload in these schools is very heavy and the teachers have to take 40 periods per week. There is no security of job and the teachers, etc. can be hired or fired at any time by the managements. There is no pension to the employees. The C.B.S.C. has no control over these institutions. They cannot take any action even if they nolice any irregularity. In the circumstances, I request the Government of India to initiate suitable steps for the uniform pay scales, service conditions, fees to be collected from the students, minimum facilities to be provided to the students and teachers, etc., pension, and streamlining the entire managements of the various categories of schools, viz., schools under C.B.S.C., matriculation schools, etc.

(iv) Need to Provide Adequate Railway Facilities to Indore, Dwas, Ujjain, Nagda, Mandsaur and Neemuch cities of Madhya Pradesh.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : देश के अनेक प्रदेशों में रेल सेवा विस्तार का कार्य उपेक्षित रहा है। मध्यप्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर इन्दौर, देवास उज्जैन, नागदा मन्दसौर, नीमच अब भी रेल सुविधाओं से वंचित हैं। इन्दौर जो कि मध्यप्रदेश का जनसंख्या के मान से भी सब से बड़ा नगर है बम्बई और अहमदाबाद से रेल यात्री सेवा से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। इस सम्बन्ध में संसद में प्रेषित याचिका और इसके उपरान्त याचिका समिति द्वारा प्रेषित अनुशंसाओं को रेल मंत्रालय ने समुचित प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया है इन्दौर से नई दिल्ली के बीच प्रारम्भ की गई बि साप्ताहिक सुपर फास्ट रेल गाड़ी में उपयुक्त प्रकार का रेक नहीं लगाया गया है। कोचेज पुराने और उपयुक्त प्रकार के नहीं हैं। उक्त रेल सेवा में सुपर फास्ट रेल सेवा के अनुरूप उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। इतना ही नहीं संसदीय याचिका समिति की सिफारिश के बावजूद इन्दौर-बम्बई के बीच सुपर फास्ट रेल सेवा अब तक प्रारम्भ नहीं की गयी है। इन्दौर और उज्जैन के बीच मीटर गेज के रास्ते से तेज गति की रेल गाड़ी चलाने की जनता की सतत मांग की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सर्वोदय एक्सप्रेस" का "स्टोपेज" जिसमें कि उज्जैन के लिए आरक्षित स्थान है नागदा में "स्टोपेज' नहीं दिया जा रहा है और इसके लिये उज्जैन से यात्रा करने वाले यात्रियों को समय और धन का व्यय कर रतलाम जाना पड़ता है जो कि असुविधाजनक है। कोटा से रतलाम के बीच छोटे स्टेशनों से यात्रा करने के लिये कोई रेल सेवा नहीं है। इन्दौर से अहमदाबाद के बीच बेज रफ्तार की रेलगाड़ी चलायी जानी चाहिये।

अतएव यह आवश्यक है कि रेल मंत्रालय उक्त मांगों की ओर ध्यान दे कर जनता को सुविधाएं उपलब्ध करावे।

(v) Need to provide adequate irrigation facilities in Mirzapur and Varanasi affected by drought and Start Job-Oriented schemes for the affected labour.

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : दुर्भाग्य का बिषय है कि हमारे उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर, वाराणसी तथा आसपास के क्षेत्रों में इस वर्ष पुनः सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। धान की बुआई और रोपाई वर्षा की कमी एवं आभाव के कारण नहीं हो पा रही है। बांध सूखे पड़े हैं। बांधों में पानी न रहने के कारण खरीफ की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। केन्द्र सरकार से मांग है कि इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायें।